पुणे। समाज में नारी के निर्णय प्रक्रिया में साझीदारी का दावा किया जाता है, लेकिन ज़्या देश के सभी हिस्सों में, समाज के सभी वर्गों में नारी को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। यह ऐसा ज्वलंत प्रश्न है, जिसका सार्थक जवाब नहीं मिल पाया है। समाज में नारी की स्थिति और संभावनाओं को लेकर निर्णय प्रक्रिया में उनकी साझेदारी को लेकर संगोष्ठी कराई गई। इसमें देश के आठ राज्यों से नारी सशज़्तिकरण के क्षेत्र में काम करने वाले 52 संगठनों की 145 महिला प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

दीनदयाल शोध संस्थान दिल्ली, रामभाऊ ज़्हाळगी प्रबोधिनी मुंबई और दृष्टी स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र पुणे के संयुज़्त तत्वधान में 26-27 अज़्टूबर 2017 को आयोजित इस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख तथा ज़्हाळगी प्रबोधिनी के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे ने स्पष्टतौर पर कहा कि नारी निर्णय प्रक्रिया के केन्द्र में रहे यह समाज में अभी तक मानसिकता नहीं बन पाई है। महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया से दूर रखने के पीछे चाहे जो कारण हो, लेकिन एक कारण जो स्पष्टतौर पर नजर आता है, वह पुरूष प्रधानता की मन:स्थिति में बदलाव नहीं आना है। उनका मत था कि प्रकृति के भेद के अलावा स्त्री-पुरूष में किसी तरह का अन्य भेद नहीं होना चाहिए। जिस तरह समाज और परिवार को चलाने में पुरूष भूमिका निभाता है, उसी तरह का काम महिला भी करती है। उन्होंने समाज में व्याप्त इस